



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042025-262199  
CG-DL-E-01042025-262199

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1453]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2025/चैत्र 6, 1947

No. 1453]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2025/CHAITRA 6, 1947

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(ईडीआई अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2025

**का.आ. 1471(अ).**—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायकी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और, भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद, केंद्रीय टूल रूम (प्रौद्योगिकी केंद्र), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थानों के प्रशिक्षण केंद्र (एमएसएमई-डीएफओ), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कयर बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एजेंसी कहा गया है) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित संभावित प्रशिक्षु को उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अधीन लाभार्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) से फीस लिए बिना कौशल विकास प्रशिक्षण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है) दिया जाता है;

और, उक्त स्कीम पर भारत की संचित निधि से व्यय उपगत किया जाता है;

और, उक्त मंत्रालय इच्छुक है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ, यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे;

अतः, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1 (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

परन्तु यदि वह व्यक्ति बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी नामांकन होना है, या रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा:

परन्तु जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, या, यदि उक्त मंत्रालय द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकारियों के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्: -

*18 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है:*

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) होती है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात्:—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जो लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से निकाला गया हो;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10<sup>वीं</sup> कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12<sup>वीं</sup> कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकों का विवरण ;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या

(v) किसी प्रवासी भारतीय नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (IV) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या
- (ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, जो उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करे, अर्थात:-
- (i) राशन कार्ड;
- (ii) जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो;
- (iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
- (iv) भारतीय पासपोर्ट;
- (v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10<sup>वीं</sup> कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12<sup>वीं</sup> कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकों का विवरण ;
- (vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाणपत्र; या
- (vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
- (I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;
- (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
- (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (IV) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या
- (viii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिषक घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार

अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज जो उक्त मंत्रालय निर्दिष्ट करे।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:

- (क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें ईआईडी शामिल होती है; तथा
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:—
- (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
  - (ii) राशन कार्ड;
  - (iii) जाति प्रमाण-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ;
  - (iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
  - (v) भारतीय पासपोर्ट;
  - (vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10<sup>वीं</sup> कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12<sup>वीं</sup> कक्षा का प्रमाणपत्र या अंकों का विवरण;
  - (vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
  - (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड ;
  - (ix) भारत में जारी किये गए ड्राइविंग लाइसेंस;
  - (x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बालक देख-रेख संस्था में रखा जाता है, ऐसे संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण-पत्र; या
  - (xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—
    - (I) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड;
    - (II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;
    - (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह प्रवासी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(xii) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या न्यास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज जो उक्त मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी धारा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,—

(क) माइआधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करें, ताकि यह पुष्टि हो सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में, तथा इस प्रयोजन के लिए, किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकेगा तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकेगा, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित है।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जब आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे का प्रतिबिंब, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, वह किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्: -

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, से किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, वहाँ उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथा स्थिति, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात्, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार-पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या जिसे एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) सम्मिलित है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), यूआईडीएआई की वेबसाइट

पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

4. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त स्कीम के अधीन किसी बालक को लाभ देने से इनकार नहीं किया जाएगा-

(i) चल रहे प्रमाणन द्वारा पहचान स्थापित करने और आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में ; या

(ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; तथा

(ख) उक्त स्कीम के अधीन लाभ, ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 की धारा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट तरीके से उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां धारा (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी उक्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखा-परीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, उक्त मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं.एस-14/1/2024-ईडीआई]

मसी एपाओ, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(EDI Section)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2025

**S.O. 1471(E).**—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the National Small Industries Corporation (NSIC), National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), Hyderabad, Central Tool Rooms (Technology Centers), training centers of Micro, Small and Medium Enterprises Development Institutes (MSME-DFO), Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (hereinafter referred to as the said Ministry) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Assistance to Training Institutions Scheme (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas, the skill development training (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the potential trainee related to Micro, Small and Medium Enterprises sector without charging fee from the beneficiaries (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, the expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Ministry is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Ministry shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Ministry for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

*For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:*

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
- (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
  - (ii) Indian passport;
  - (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10<sup>th</sup> class or higher secondary or 12<sup>th</sup> class, issued by a recognised board of school education;
  - (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
  - (v) In respect of a foreign national,—
    - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
    - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
    - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
    - (IV) if he is other than an Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
- (i) Ration card;
  - (ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
  - (iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
  - (iv) Indian passport;
  - (v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10<sup>th</sup> class or higher secondary or 12<sup>th</sup> class, issued by a recognised board of school education;

- (vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (vii) In respect of a foreign national,—
  - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
  - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
  - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
  - (IV) if he is other than an Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) Any other document as the said Ministry may specify.

*For beneficiaries aged 18 years or above to whom an Aadhaar number has not been assigned:*

- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
  - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
  - (ii) Ration card;
  - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
  - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
  - (v) Indian passport;
  - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10<sup>th</sup> class or higher secondary or 12<sup>th</sup> class, issued by a recognised board of school education;
  - (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
  - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
  - (ix) Driving licence issued in India;
  - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
  - (xi) In respect of a foreign national,—
    - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
    - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
    - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
    - (IV) if he is other than an Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a



national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

- (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xiii) Any other document as the said Ministry may specify.

(4) An officer designated by the said Ministry in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the EID on MyAadhaar Portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
  - (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
  - (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

- (a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
  - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
  - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
- (b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
- (c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the said Ministry.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or above are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the said Ministry shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19<sup>th</sup> December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-14/1/2024-EDI]

MERCY EPAO, Jt. Secy.